

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 10 | अंक : 38 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 1 सितंबर, 2023 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 12 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHN/2014/56526

पीयूष हजारिका का आदर्श दुश्सासन : भूपेन बोरा पेज 3

केन्या ने भारत से तोप, लडाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और जहाज खरीदने में रुचि दिखाई पेज 4

तीसरी नजर से पकड़े गये अपराधियों का कर्ते प्रचार, इससे बढ़ी दहशत : मुख्य सचिव

पंजाब में आईसआई समर्थित गौंग के छह गुणे गिरफ्तार, हथियार बरामद पेज 8

बाल विवाह के खिलाफ अभियान इसी माह से शुरू : सीएम

गुवाहाटी। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान सिंतंबर में फिर से शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री हमें तिथि शुरू किया जाएगा, आपसां अभियान से राज्य भर में हंगामा मच गया था, जब असम में अधिक लोगों को बाल विवाह में शामिल होने के



आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुवाहाटी को मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने 28 जुलाई को पुलिस अधीक्षकों के बांध समेलन में अधिकारियों को एक और अभियान शुरू करेंगे और 31 अगस्त तक बाल-विवाह के आरोपियों से निपटने के लिए विशिष्ट संचालन प्राक्रिया तैयार करेंगे। उन्होंने कमज़ोर

स्वास्थ्य विभाग की दवा से दर्जनों छात्र बेहोश

विश्वनाथ (हि.स.)।

विश्वनाथ जिला स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार से फाइलेरिया के उन्नत लेन अभियान शुरू किया। लेकिन, इस अभियान की शुरूआत में ही गड़बड़ी हो गई। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में फाइलेरिया के उन्नत लेन के लिए छात्रों को मुफ्त दाएँ प्रदान की। लेकिन, विश्वनाथ घाट के फखरान अली अहमद हाई स्कूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गई मुफ्त डीईसी और एक्बेंडोजोल को गोलियां खाने के बाद 50 से अधिक छात्र स्कूल में बेहोश हो गए। इससे तुरंत स्कूल में डेहोश की स्थिति पैदा हो गई। स्कूल प्रशासन और अभियाकारी ने छात्रों को तुरंत विश्वनाथ चाराली सब-डिविजनल सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। स्थानीय लोगों



-शेष पृष्ठ दो पर

भागवत आज से तीन दिनों तक असम में

विशेष सत्र में मोदी सरकार ला सकती है एक देश-एक चुनाव का बिल

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने

18 से 22 सितंबर तक संघर्ष के विशेष सत्र बुलाने का एलान किया है। भूतों के संघर्ष-एक देश-एक चुनाव का बिल ला सकती है। हालांकि, एक देश-एक चुनाव के लिए अनुच्छेद-83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव समय से पहले भर्ती करा देते हैं। उनका तर्क है कि इस कदम से विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हैं। लोकसभा चुनाव भी अगले साल के मध्य में हो सकता है।



एक देश-एक चुनाव का विचार कम से कम 1983 से ही अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। हालांकि, 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आया था। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भर्ती होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा समय से पहले भर्ती गई और 1971 में नए चुनाव लाल चाहे राजनीति के लिए समय भी बचेगा। इस साल चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हैं। लोकसभा चुनाव भी अगले साल के मध्य में हो सकता है।

-शेष पृष्ठ दो पर

पूर्वाञ्छल कृष्णी
(असमीजा दैनिक)

PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)

GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

मोबाइल फोरेंसिक लैब को हरी झंडी दिखाई



गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय परिसर में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई दिया। यह मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशाला गन्धी ने अनुसार नमूनों की जांच कर सकेगा।

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को असम सचिवालय प

संपादकीय

क्या आम चुनाव अपने तय समय से पहल दिसंबर-जनवरी में कराए जा सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूरे देश को नया जनादेश देना है। हालांकि सरकार और भाजपा को भीतरी संकेत ऐसे नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि वह जनादेश का सम्पादन करते हैं, लिहाजा वह पूरी अवधि तक प्रशासन में रहेंगे और चुनाव तय वक्त पर ही कराए जाएंगे, लेकिन विषय के बड़े नेताओं नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने मध्यवर्धी चुनाव की आशंका जताई है। दोनों क्रमशः बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। खुफिया सूचनाएं उन तक भी पहुंचती हैं। दोनों नेताओं ने 'ईंडिया' गढ़बंधन को जल्द ही एकजुट करने और साझा रणनीति तय करने के आग्रह किए हैं। ममता बनर्जी का इतना दावा भी है कि चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति हो सकती है कि विषयकी गठबंधन आकार भी न लेने पाए और चुनावों का शांखनाद कर दिया जाए। विषयकी नेताओं की दलीलें हैं कि जिस तरह मोदी सरकार ने रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया है और 'उज्ज्वला योजना' वालों को 400 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलेगा। इसी के साथ यह भी घोषणा की गई है कि 75 लाख महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और भरा गैस सिलेंडर भी

विपक्षी नेताओं की दलीलें हैं कि जिस तरह मोदी सरकार ने रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया है और 'उज्ज्वला योजना' वालों को 400 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलेगा। इसी के साथ यह भी घोषणा की गई है कि 75 लाख महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और भरा गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इससे लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। यह मोदी सरकार का ही दावा है। इन घोषणाओं को 'राखी का तोहफा' प्रचारित किया जा रहा है। बहरहाल भारत में रसोई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की कुल संख्या 33 करोड़ से कुछ अधिक है, लिहाजा 'उज्ज्वला' के लाभार्थियों की संख्या बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भाजपा नेतृत्व ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में पराजित सीटों पर अभी से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वे चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि भाजपा नेतृत्व ने अपने पार्टी काडर को अलर्ट भी कर दिया है और बूथ स्तर के असंख्य कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं।

लिहाजा चुनाव अप्रैल-मई के तय वक्त पर ही होंगे। दरअसे गठबंधन अभी तक एक निश्चित आकार और ताकत ग्रहण नहीं मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को 'इंडिया' की बैठकें होनी चाहीं कि गठबंधन का अध्यक्ष, संयोजक तय होने के साथ-साथ सीटों के बंटवारे का शुरुआती फैसला होता है अथवा नहीं। गठबंधन न्यूनतम कार्यक्रम भी बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय नहीं होगा, क्योंकि अपने-अपने प्रभाव के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री अपने-अपने नेता के शोर मचाए जा रहे हैं। संभव है कि नीतीश चुनाव का हव्वा खड़ा कर दबाव देने की कोशिश कर रहे हों तो निर्णय जल्द हो जाएं और 'इंडिया' का साझा चुनाव प्रचार अपने सके। बहरहाल कारण कुछ भी हों, लेकिन राजनीतिक गलियाँ छिड़ गई हैं कि क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ऐसे चुनाव और अप्रत्याशित नहीं होते, क्योंकि 1971, 1980, 1984, 1999 और 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विभिन्न कारणों द्वारा चुनाव करा चुके हैं। उनकी जीत भी हुई और उनके दल पर बहरहाल मौजूदा परिदृश्य बिल्कुल भिन्न है। हम सरकार के नियन्त्रण में रखे रहेंगे। जहां तक विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उपर सवाल है, इस विषय में अभी वहां एकता नहीं हो पाई है। कोई अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहिए, कोई राहुल गांधी चाहता है, तो कोई ममता अथवा नीतीश का नाम भी ले रहा है।

ਕੁਛ ਅਲਗ

दोषी है आंगन का पेड़

इन पेड़ों के पक्ष में बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे फैसलों की जड़ में आरामदार हाइमाचली के जीवन की मुश्किलें समझी नहीं जातीं। आपदा से राहत होने के बाद यहाँ वासी अपनी जीवन की अचूती को भूल देते हैं, जो सामान्य लोगों के लिए किंतु आफत से कम नहीं। अहम फैसलों में कई स्टेन क्रशर बंद कर दिए गए हैं, पर्यावरणीय लिहाज से ऐसे फैसलों की गूंज से सकारात्मक शाबाशिया मिल जाती है। लेकिन क्या विज्ञान की दृष्टि से यह सामाजिक न्याय की एकमात्र छड़ी है? कुछ लोग इसी तरह पर्यावरण संरक्षण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए छड़ी खोलते हैं, जिसके फैसलों के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। अब आपके घर का आम वन विभाग की टोकरी में होगा, तो त्रियांबल, तुनी, पदम वरीठा भी घर के मालिकाना हक कहीं अधिक जंगलात की अनुमतियों की पैदाइश करेगा। पर्यावरण संबंधी और भी कई फैसले हिमाचल की जीवनशैली में नशरत की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन इनसान से पेड़ों का रिश्ता घटा क्यों, इसकी चर्चा नहीं होती। किसी ने आज तक यह विशेषण नहीं किया कि हिमाचल के नागरिकों को वन संरक्षण के बदल मिलता क्या है। आज से पचास साल पहले की वास्तुकला को देखें, तो हिमाचल उस स्तर तक लकड़ी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हम मजबूरन ऐसी इमारतें बना रहे हैं जिनकी बनावट में कम से कम लकड़ी का प्रयोग और अधिकतर स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमीनियम को खपाया जा रहा है। कभी धज्जी निर्पात्र शैली से घर बनते थे, लेकिन आज चाहकर भी कोई इसे अपना नहीं सकता। क्यों? हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति में परंपरागत नींव के पथर आज की स्थिति उपलब्ध हो सकते हैं। पहले खड़ा या दरियाओं को छान कर भवन निर्माण करना सामग्री उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन आज घर का निर्माण एक ऐसी गणना है, जिसके लिए हिमाचल के बूते पूरी नहीं होते। बेशक हम स्तर फीसदी जमीन पर जंगल उगाते हैं, लेकिन घर की छांव के लिए बाजार में उपलब्ध आयातित इमारती लकड़ी वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। बसियों में जंगल धूम सकता है, लेकिन बस्ती को जंगल की तरफ देखने की मनहाली है। हिमाचल में घर बनाना एक अपराध की तरह विभिन्न विभागों के चक्कर काट रहा है। ऐसे को विभाग नहीं, जो जनता की मांग पर ऐसी भूमि की शिनाख्त कर सके। शहर के विकास विभाग या इसकी किसी एजेंसी ने मांग के आधार पर कोई नया शहर नहीं बसाया। करीब एक दशक पूर्व हिमुडा ने आवासीय मांग पर घर का सपाया दिखाया, लेकिन पचहतर हजार के करीब आए आवंदन आज भी भ्रमित है। राजस्व रिकाई में टुकड़ों में बंटी जमीन का सौदा हो जाए, तो निर्माण की पैमाइश में बिजली या पेयजल की आपूर्ति के लिए युद्धरत माहाल कोर्ट कहरी में बूढ़ा कानून देता है। क्या कभी अंदाजा लगाया कि अपना घराँदा बनाने की ख्वाहिश ने कितने लोगों को कानूनों की जिरह में फंसा दिया है। इस पर तुरा यह कि अगर कोई पुरुष तैनी टुकड़ा मिल भी जाए, तो 16 प्रजातियों के पेड़ इतनी निगरानी तो कर लेंगे कि किसी का घर एक जन्म में पूरा न हो। बेशक आपदा के वर्तमान दौर से बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन क्या हम हिमाचली जनता की मांग और आपूर्ति के बाद वन विभाग को न्यायाधीश बना कर न्याय कर रहे हैं।

બાળ કાવ્ય

1

प्रथा जमाने में आपको अपनी पुरानी सोच का परित्याग करना पड़ेगा। जो कल अच्छा था वह अब समय बीतने के साथ बोसीदा हो गया है। अब इसे सुधारने का प्रयास करोगे, तो ऐसे लोगों कि जैसे आप अपने उधड़े हुए कोट के बखिये रमण्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मरण्मत को क्या कहें? एक ओर से बखिया सीते हैं तो दूसरी ओर से उधड़ जाता है। क्यों न जो कोट इन सदियों जैसे बरसों से हम पर लदा है और हमें फटीचर हो जाने का एहसास करवा रहा है, जी हाँ, क्यों न इसे उठाकर एक ओर फेंक दिया जाए और इसकी जगह एक बिल्कुल नया कोट पहन लिया जाए। मासा अल्लाह। बात देश के अस्सी प्रतिशत लोगों की गरीबी या उनकी बढ़ती महंगाई की मार या उन पर लदे बेकारी के बढ़ते बोझ को घटाने की हो रही थी, और आप फटे पुराने कोट की उधडन सीने की जगह नये कोट की तलाश में चल दिये। अजी हम कहां चले हैं? यह बेनर आंखें और बेसहारा कदम ही नई जिंदगी की तलाश में भटक कर हमें बताते हैं कि अरे, पुराने फटे कोटों की उधडन को रो रहे हो, अपनी मैली कमीज और फटी बनियान की फिक्र करो। कहीं वह भी नदारद न हो जाये। क्योंकि इसकी

एक उधडे कोट की मरम्मत

मौजूदा हालत में तो इसे कोई गिरवी रख कर भी आपको एक जून पेट भरने का वासीला देने से रहा बहुत बरस पहले जब इस देश में आजादी के चिराम जल थे, तब देश के मसीहाओं ने फैसला किया था कि सरकारी उद्यम और निवेश, और लाला लोगों का निजी व्यापार-धंधा आपस में गलबहिंयां डाल कर चलेगा। जीवन की भीख मांगते पिछड़े लोगों का खाली ओसारा सरकारी क्षेत्र अपने लाभ की परवाह किये बगैर जनकल्याण से भरेगा।

ऊंची अटारियों वाला निजी क्षेत्र बढ़ते लाभ की पताका फहराने की धून में देश को प्रगति की ऐसी दौड़ देगा कि ये अटारियां चाहे और कितनी ऊंची हो जाएं, इनकी खिड़कियों से गिरता दाव सौगात बन विचित्रों के नंगे कंधों पर नया कोट बन कर लद सकेगा। जनाब फिर साल दर साल पंचर्वष्याय योजना बन कर गुजरते गये। निजी क्षेत्र की अटारियां रूप बदल कर बहुमंजिले मॉल-प्लाज़ा बन गये। गरीब के कन्धों का वह एहसास भी खत्म हो गया कि उसके कन्धों पर कोई फटा हुआ कोट कभी रहा है। रफूगर किस उधारी हुई सीन को सिये? वहां तो कोई कोट ही नहीं रहा। हां, बाबूडम की रियासत जरूर बन गई। सरकारी उद्यम की कारगुजारी और उसके द्वारा फहरायी

जाने वाली कल्याण पताका एक ऐसी कटी पतंग बनी, जो उनकी बस्तियों के ऊपर से गुजरती है। डिजिटल तरंगों में उलझ कर रह गई। क्या कहा इस बीच जमाना कथामत की चाल चल गया आनलाइन हो गया।

लेकिन उसका परिसर लकड़क बस्तियों की सीमायें न लांघ पाया। शेष देश इतने बरसों रोटी कपड़ा और मकान वाले अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा था, वह आनलाइन हो सकने की चाहत के साथ स्मार्ट फोन बंटने की खीराती कतार में लग गयी लीजिये, ऐसी प्रगति न घर की रही न घाट की 'आनलाइन' होकर डिजिटल हो जाने का न कंगूरा क्या छूते? यहां तो 'ऑफ लाइन' की पटरी भी उतर गये। अभी बड़े लोगों के नये चिन्नन ने ए पैगाम दे दिया। आक्सफैम के सर्वेक्षण आंकड़े प्रमत जाओ कि महामारी के सैलाब में दस प्रतिशत अरबपति तो खरबपति हो गए, और नब्बे प्रतिशत अपने पुराने तार-तार हो गए कोटों के लिए रफून तलाश रहे हैं। लेकिन इनको मंदी लग गयी है। जब उनके लिए नये कपड़े ही नहीं बिकेंगे, तो रफूगर चौराहों पर जमा भिखारी बिग्रेड में शामिल होकर अपने लिए रोटी तलाशने का नया धंधा अपना ले तो क्या करें।

सकता है। चांद पर उपलब्ध पानी (वर्फ की सिल्लियों के रूप में) मंगल ग्रह पर जाने वाले यानों के काम आ सकता है, क्योंकि चांद को भविष्य में एक अंतरिक्ष अड्डे के रूप में विकसित किया जा सकता है वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चंद्रमा पर इतने गहरे गड्ढे भी हैं, जहां अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और इन क्षेत्रों में तापमान आश्वर्यजनक रूप से माइनस 248 डिग्री सेल्सियस (-414 फारेनहाइट) तक पिर जाता है। यहां चंद्रमा की सतह को गर्म करने वाला कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की इस पूरी तरह अज्ञात दुनिया में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है और नासा के मुताबिक, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रहस्य, विज्ञान और उत्सुकता से भरा है। हाल फिलहाल चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में विश्व के विकसित देश बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। आज यूरोप, रूस और अमेरिका और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर पहुंचना चाहती हैं क्योंकि चांद पर पृथ्वी की भाँति एक कॉलोनी बनाने की संभावना दिखती है और आने वाले समय में मंगल पर जाने के लिए भी चांद एक अहम स्थान या स्टेशन के रूप में विकसित हो सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में चांद पर अमेरिकी यान अपोलो के उत्तरने से पहले ही वैज्ञानिकों ने संभावना जाहिर कर दी थी कि चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन 1960-70 के दशक में अपोलो अभियान के जरिए चांद से मिट्टी के जो नमूने लाए गए थे, वे सब सूखे थे और उनमें पानी नहीं था। इसके बाद, वर्ष 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उन नमूनों का आधुनिक तकनीक से दुबारा गहन विश्लेषण और अध्ययन किया तो यह पाया गया कि उसमें हाइड्रोजन की मौजूदगी थी। वास्तव में यह हाइड्रोजन ज्वालामुखी की राख में चमकदार शीशों के भीतर मिली थी। इसके बाद भारत ने वर्ष 2008-09 में चांद पर पानी की मौजूदगी बताई। वर्ष 2009 में नासा ने भी एक अन्य अभियान चांद पर भेजा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उत्तरा, लेकिन उसने ऊपर से तस्वीरें ले लीं और उस अभियान ने चांद की सतह के नीचे वर्फ का पता लगाया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 1998 में नासा का लुनार प्रॉस्पेक्टर भी चांद का चक्कर लगाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर छाया में छिपे गड्ढे में वर्फ की जानकारी जुटा चुका था। हाल फिलहाल चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उत्तर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है, अब उम्मीद जताई जा सकती है कि चंद्रयान पानी के बारे में और भी सबूत खोज सकता है। यदि भारत इस बार फिर चांद पर पानी को लेकर कोई खुलासा करता है तो दुनिया भारत की इस रिसर्च का निश्चित रूप से अनुशरण करेगा, क्योंकि चांद को अब एक कालोनी के रूप में विकसित करने की ओर संपूर्ण विश्व की नजरें हैं।

चिकित्सा विज्ञान को खूबियां-खामियां

आधुनिक

से चिकित्सा जगत से जुड़े लोग लाखों-करोड़ों मरीजों को जीवनदान दे रखे हैं। चिकित्सा जगत के शोध हमें नई राह दिखाते हैं और जीवन कुछ और आसान हो जाता है। आइए, चिकित्सा विज्ञान में हुए शोध की कुछ मुख्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चिकित्सा विज्ञान मानता है कि हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर है और अस्सी प्रतिशत बीमारियों को ये खुद ही ठीक कर सकता है, बिना किसी दवाई के। वस्तुतः: आयुर्वेद तो यह भी कहता है, कि आम बुखार और सिरदर्द जैसी बीमारियां, जिन्हें हम बीमारी मानते हैं, बीमारी हैं ही नहीं बल्कि ये शरीर की किसी अन्य खराबी का संदेश देते हैं। ये सिफ संदेशवाहक हैं और दवाई लेकर हम इन संदेशवाहकों को चुप करता देते हैं, उनका संदेश सुनते ही नहीं और असल रोग ठीक होने के बजाय अंदर ही अंदर पनपता चलता है जो बाद में कहीं ज्यादा कष्टप्रद रोग के रूप में सामने आता है। चिकित्सा विज्ञान यह मानता है कि बुखार को यदि बर्दाश्त करके खाने-पीने में उचित परहेज कर लिया जाए तो बुखार दो-तीन दिन में खुद ही ठीक हो जाता है और बुखार के कारण शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे हम आने वाली बड़ी कठिनाई से मुक्ति पा लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान यह भी स्वीकार करता है कि अस्सी प्रतिशत बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान सेल्फ लिमिटिंग डिसीजिज मानता है, यानी ये बीमारियां ऐसी हैं जो ज्यादा बिगड़ती नहीं हैं, अतः इनके इलाज के लिए दवाई की नहीं बल्कि धीरज, आराम और परहेज की जरूरत होती है। दवाई लेकर तो हम दरअसल बीमारी को और बढ़ाते हैं क्योंकि दवाई से बुखार दब जाता है और शरीर को अपनी सफाई का मौका नहीं मिल पाता। चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह स्वीकार करना है कि अस्सी प्रतिशत बीमारियों का कारण हमारी भावनाओं से जुड़ा है। बचपन में या बाद में कभी भी निरंतर अपमान सहने, मारपीट सहने, चिढ़ाए जाने आदि के बाद उसका प्रतिकार न कर पाने के कारण अगर हम खुद को बेबस पार्थे तो हमारे मन को जो चोट लगती है वह हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाती है और उससे उपजी आत्मगलानि, जीवन में किसी न किसी रोग के रूप में सामने आती है। लेकिन यही शोध चिकित्सा विज्ञान की एक बड़ी असफलता की ओर भी इशारा करता है। चिकित्सा विज्ञान की कोई भी प्रणाली भावनात्मक घावों को समझने और ठीक कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ है। दावा चाहे कुछ भी किया जाए, एलोपैथी, हाय्मोपैथी, आयुर्वेद या विश्व में प्रचलित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियां, कोई भी प्रणाली

एक शरीर के इलाज तक हा सामना हा। उच्च शिक्षा नेचिकित्सक भी मन में हुपे थावों का सही इलाज कर ही पाये तकी कोई गरंटी नहीं है। यही वह मुकाम है जहां आकर हम आध्यात्मिक उपचार की महत्ता समझ में आती है, पर हम आध्यात्मिक उपचार की बात करें, उससे पहले चिकित्सा विज्ञान कुछ और मान्यताओं पर भी बात कर लेना उपयोगी होगा। हमने नहीं ही है कि हमारी भावनाओं का हमारी सेहत से गहरा रिश्ता है। और प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्लैसीबो ईफैक्ट भी दवाई की तरह काम करता है, यानी, अगर किसी रोगी को यह हाएँ कि उसे दवाई दी जा रही है और दवाई की जगह सदा नी, चीनी या नमक, या कुछ भी ऐसा दे दिया जाए, तो भी रोगी न तसल्ली से ही ठीक होना शुरू हो जाता है कि उसे रोग का दवाई मिल गई। इसी तरह यह भी सिद्ध हो चुका है कि यदि रोगी के अपासपास के वातावरण को खुशनुमा बना दिया जाए, रोगी के मन-आशा का संचार किया जाए, तो बहुत संभव है कि रोगी अपने भूसी अत्यंत गंभीर रोग से भी उबर जाए, जल्दी ठीक होना शुरू हो जाए, तेजी से ठीक होना शुरू हो जाए, या उसकी प्रतिरोधक मता बढ़ जाए और वह डाक्टरों की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबावन जीने के काबिल हो जाए। इसके विपरीत यदि किसी रोगी ने डाक्टर ये बताएँ कि उसका रोग इतना गंभीर है कि वह कुछ ही नहीं का मेहमान है, तो यह बाकायदा संभव है कि उसकी निराशा के कारण उसकी शारीरिक हालत और बिंगड़ा और वह रोगी अपने समय से बहुत पहली ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक बड़ा सच यह भी है कि चिकित्सा विज्ञान की अब तक को प्राप्ति के बावजूद, यह स्वयंसिद्ध है कि चिकित्सा की कोई प्रणाली शात-प्रतिशत सफल नहीं है, अतः किसी डाक्टर, हकीम, प्राकृतिक चिकित्सक या वैकल्पिक चिकित्सक नाली से जुड़े चिकित्सक को एक से अधिक चिकित्सकों नालियों में महारत हासिल है तो रोगी को उससे ज्यादा लाभ लेने की संभावना सबसे ज्यादा है, और यदि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली का भी पोषक हो तो उसकी हारत का स्तर कई गुण बढ़ जाता है। कारण यह है कि चिकित्सा विज्ञान की पहुंच सिर्फ शरीर तक है जबकि अधिकांश बीमारियों का कारण मानसिक है और एक सीमा के बाद पारंपरिक नेचिकित्सक भी बेबस हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी शिक्षा साथ आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान भी शामिल हो एतो सोने पर सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा शरीर की कार्यप्रणाली की जानकारी देती है और आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली एक चिकित्सक के लिए रोगी के वचेतन मन का दरवाजा खोल देती है।

दश दुनाया स

प्रदेश का ढंड राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं?

५

माह की प्रलयंकारी बारिश ने प्रदेश के लोगों व प्रदेश के मर ही तोड़ दी। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप आज तक किसी नहीं देखा होगा। बारिश बाढ़ बनकर ही बरसने लगी है। इसमें व पर्यावरण में हुए बदलावों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश अर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ राज्य है व बागवानी ही लोगों की अर्थकी के प्रमुख साधन हैं। आपदाग्रस्त लोगों को हर तरफ से संबल प्रदान करने की ज़रूरत है। लगता है कि हिमाचल प्रदेश विकास में कम से कम पीछे पहुंच गया है। अगस्त का प्रलयंकारी माह सैकड़ों लील गया। मृतकों का आंकड़ा 400 तक पहुंचने लगा। बाजान, सरकारी भवन व सरकारी विद्यालय जर्मीनोज हो गए। घर व बेबस नजर आ रहे हैं। जमीनें पिघलती हुई नजर बागीचे भयंकर ते धग मे अटश्य

हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ राज्य नहीं है। खेती व बागावानी ही लोगों की आर्थिकी के प्रमुख साधन हैं। आज प्रदेश के आपदाग्रस्त लोगों को हर तरफ से संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। लगता है कि हिमाचल प्रदेश विकास में कम से कम 10 से 15 वर्ष पीछे पहुंच गया है। अगस्त का प्रलयांकारी माह सैकड़ों लोगों की जानेलील गया। मृतकों का आंकड़ा 400 तक पहुंचने लगा है। सैकड़ों मकान, सरकारी भवन व सरकारी विद्यालय जमींदोज हो गए हैं। लोग बेघर व बेबेस नजर आ रहे हैं। जमीनें पिघलती हुई नजर आ रही हैं। बागीचे भयंकर तबाही के चलते धरा से अदृश्य होने लगे हैं। जन संपर्क मार्ग भारी क्षतिग्रस्त हो यह आफत लेकर

स्वाभाविक है हैं तो कहीं अवरुद्ध पड़े हैं।
इस तांडव से

नव जाति कुछ सीख तो अवश्य लेनी और पूर्व में हुई
हीं दोहराना चाहेगी। पिछले 40-50 वर्षों से स्थानीय
खेलों के केगार पर आ गए थे और लोगों की हिम्मत भी
के बहुत समीप और कई जगह अतिक्रमण के चलते
पारे व नालों-खड़ों में मकान बनाने का प्रचलन भी बन
इसी सोच के चलते कई जानों व मकानों का जल प्रवाह
में पानी की नमी इतनी ज्यादा हो गई कि अपने ऊपर
दा बजन को सहने की क्षमता क्षीण होने लगी है। सड़क,
में पानी की निकासी की व्यवस्था गायब ही है, जो पानी
तरे नदी-नालों व खड़ों में तुरंत पहुंच जाता था। आज हर
भी अवशेषित हो रहा है। यह बरसात मनुष्य को बहुत
र मजबूर कर गई। आपदा की सच्चाई कुछ भी हो, हर
न से हिमाचल प्रदेश में आपदा का स्तर बहुत बड़ा हो
लए इसे अविलंब राष्ट्रीय आपदा घोषित कर विशेष
ता प्रदान करना लाजिमी है। इस दिशा में बैवजह देरी
। इस त्रासदी में कई यों की जानें बचाई जा सकती है, यदि
का यों को जल्दी ही गति मिल सके। राष्ट्रीय आपदा के
मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। इंडिया टीवी में
अनुसार दसवें वित्त आयोग में जब राज्य की एक-तिहाई
वत होती है, तब आपदा की दुर्लभ गंभीरता को राष्ट्रीय
ता है, मगर दिसंबर 2005 में देश में आपदा से निपटने
यापी कानून पास हुआ जिसमें किसी भी इलाके में
मानव निर्मित कारणों से दुर्घटना या उपेक्षा की वजह से
महाविपत्ति, अतिष्ठ तबाही आदि जिसमें मानव जीवन
पंपति को भारी नुकसान और विनाश या पर्यावरण को
और ये इतने बड़े पैमाने पर हो जिससे स्थानीय समुदाय
ना संभव न हो, वो आपदा होगी।

